

ओपी सिंह

आईपीएस

डीजी परिपत्र संख्या- 9 /2019

पुलिस महानिदेशक,
उत्तर प्रदेश

1-तिलकमार्ग, लखनऊ-226001

दिनांक: फरवरी 8, 2019



विषय: मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका(सी) संख्या-565/2012 निपुन सक्सेना व अन्य बनाम यूनियन आफ इण्डिया व अन्य में निर्गत निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने के सम्बन्ध में।

प्रिय महोदय,

आप सभी इस तथ्य से भली-भाँति अवगत है कि आज भी यौन उत्पीड़न से पीड़ित महिला को समाज में उपहास, तिरष्कार, अवहेलना एवं सामाजिक और पारिवारिक वहिष्कार के अपमान का भी सामना करना पड़ता है। इन्हीं वास्तविकताओं के दृष्टिगत भारतीय विधायिका द्वारा ऐसे अपराधों से पीड़ितों की पहचान के प्रकटीकरण को भारतीय दण्ड विधान की धारा 228ए के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध घोषित किया गया है। इसी प्रकार POCSO अधिनियम की धारा 23 के अन्तर्गत यौन उत्पीड़न से पीड़ित की प्रतिष्ठा हनन एवं उसकी गोपनीयता के अतिलंघन का निषेध विषयक प्राविधान किया गया है, साथ ही अधिनियम की धारा 37 के अन्तर्गत पोक्सो अधिनियम से आच्छादित अपराधों का विचारण बन्द कमरे में किये जाने की व्यवस्था की गयी है।


सन्दर्भित रिट याचिका में मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा बालकों एवं महिलाओं के हित तथा न्यायहित में निर्णय की तिथि से 01 वर्ष के अन्दर प्रत्येक जनपद में "One Stop Centre" Setup के साथ निम्न निर्देश निर्गत किये गये हैं :

43. In view of the aforesaid discussion, we issue the following directions :-

- 1. No person can print or publish in print, electronic, social media, etc. the name of the victim or even in a remote manner disclose any facts which can lead to the victim being identified and which should make her identity known to the public at large.*
- 2. In cases where the victim is dead or of unsound mind the name of the victim or her identity should not be disclosed even under the authorization of the next of the kin, unless circumstances justifying the disclosure of her identity exist, which shall be decided by the competent authority, which at present is the Sessions Judge.*
- 3. FIRs relating to offences under Sections 376, 376A, 376AB, 376B, 376C, 376D, 376DA, 376DB or 376E of IPC and offences under POCSO shall not be put in the public domain.*
- 4. In case a victim files an appeal under Section 372 CrPC, it is not necessary for the victim to disclose his/her identity and the appeal shall be dealt with in the manner laid down by law.*
- 5. The police officials should keep all the documents in which the name of the victim is disclosed, as far as possible, in a sealed cover and replace these documents by identical documents in which the name of the victim is removed in all records which may be scrutinised in the public domain.*

6. All the authorities to which the name of the victim is disclosed by the investigating agency or the court are also duty bound to keep the name and identity of the victim secret and not disclose it in any manner except in the report which should only be sent in a sealed cover to the investigating agency or the court.
7. An application by the next of kin to authorise disclosure of identity of a dead victim or of a victim of unsound mind under Section 228A(2)(c) of IPC should be made only to the Sessions Judge concerned until the Government acts under Section 228A(1)(c) and lays down a criteria as per our directions for identifying such social welfare institutions or organisations.
8. In case of minor victims under POCSO, disclosure of their identity can only be permitted by the Special Court, if such disclosure is in the interest of the child.
9. All the States/Union Territories are requested to set up at least one 'one stop centre' in every district within one year from today.

आप सभी से अपेक्षा की जाती है कि सन्दर्भित रिट याचिका में पारित आदेश दिनांकित 11.12.2018 का भली-भाँति अध्ययन एवं परिशीलन करके अधीनस्थ पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों को अवगत कराते हुये मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्गत उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन करना एवं कराना सुनिश्चित करायें।

भवदीय,

 (ओ०पी० सिंह)

समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक,
 प्रभारी जनपद,
 उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित—

1. प्रमुख सचिव(गृह), उ०प्र० शासन।
2. पुलिस महानिदेशक, सीबीसीआईडी, उ०प्र० लखनऊ।
3. अपर पुलिस महानिदेशक, जीआरपी, उ०प्र० लखनऊ।
4. अपर पुलिस महानिदेशक, महिला सम्मान प्रकोष्ठ, उ०प्र० लखनऊ।
5. समस्त जोनल अपर पुलिस महानिदेशक, उ०प्र०।
6. समस्त परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/उपमहानिरीक्षक, उ०प्र०।